

साप्ताहिक

मालव आंचल

वर्ष 47 अंक 41

(प्रति रविवार) इंदौर, 30 जून से 06 जुलाई 2024

पृष्ठ-8

मूल्य 3 रुपये

बजट में युवा, गरीब, महिला, किसान सहित सभी वर्गों का रखा गया है ध्यान : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने वर्ष 2024-25 के बजट को सर्वजन हिताय-सर्वजन सुखाय बताया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पहली बार 03 लाख 60 हजार करोड़ से अधिक की राशि का बजट प्रस्तुत किया गया है। बजट की यह विशेषता है कि इसमें किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगाया गया है। किसी भी विभाग की अपेक्षित राशि को कम नहीं किया गया, अपितु सभी विभागों के आवंटन में वृद्धि की गई है। विकसित भारत-विकसित मध्यप्रदेश की थीम पर प्रस्तुत बजट में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अपेक्षा अनुसार जीडीपी की ग्रोथ को सुनिश्चित करते हुए आगामी पाँच वर्षों में बजट का आकार दोगुना किया जाएगा।

बजट में सभी वर्गों विशेषकर युवा, गरीब, महिला, किसान आदि का ध्यान रखा गया है। आईटी सहित नवीन तकनीक के क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देते हुए प्रशासनिक सेवाओं में प्रदेश के युवा अधिक से अधिक संख्या में आए, इस उद्देश्य से उन्हें प्रोत्साहन व प्रशिक्षण उपलब्ध कराने तथा प्रदेश में उनका योगदान बढ़ाने के लिए दीर्घगामी योजना पर कार्य होगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने वर्ष 2024-25 के बजट के लिये प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव विधानसभा स्थित मीडिया सेंटर में मीडिया प्रतिनिधियों से चर्चा कर रहे थे।



मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि जो विद्यार्थी छात्रावासों में अध्ययनरत हैं, उनके लिए भी बजट में विशेष व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में दुग्ध उत्पादन के प्रोत्साहन के लिए बजट में पर्याप्त धन राशि की व्यवस्था की गई है। गौ-शालाओं के लिए भी पर्याप्त राशि का प्रावधान किया गया है। औद्योगिक विकास के लिए बजट प्रावधान में 40 प्रतिशत की

वृद्धि की गई है। भारी उद्योग, एमएसएमई और कुटीर उद्योग सहित स्व-सहायता समूह के लिए भी बड़ी राशि का प्रावधान किया गया है। स्थायी प्रकृति के निर्माण कार्य जैसे स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, सड़क, एक्सप्रेस-वे पर विशेष ध्यान होगा। महाकौशल, चंबल, विंध्य, मालवा, आदि की सीधी कनेक्टिविटी राजधानी से जुड़े, इस उद्देश्य से पर्याप्त व्यवस्था करते

हुए वित्तीय तरलता का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में सिंहस्थ का वृहद स्तर पर आयोजन होने वाला है। उज्जैन में होने वाला सिंहस्थ भव्य और दिव्य होता है। सिंहस्थ के लिए इंदौर एवं उज्जैन संभाग के 13 जिलों के देव-स्थानों पर पर्याप्त व्यवस्था के उद्देश्य से टोकन राशि के रूप में 500 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि वरिष्ठ नागरिक प्रदेश की थाती हैं, उनके लिए विशेष योजना आरंभ की जा रही है। अन्य प्रदेशों या विदेशों में कार्यरत युवाओं के माता-पिता की देखरेख के लिए नगरीय क्षेत्र में ऐसी सोसायटियों को प्रोत्साहित किया जाएगा, जहाँ वरिष्ठ नागरिकों के लिए चिकित्सा सुविधा सहित सभी आवश्यक व्यवस्था हो। इस दिशा में आगे आने वाले प्रायवेट सेक्टर को राज्य शासन की ओर से सहयोग उपलब्ध कराया जाएगा।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में रिकार्ड संख्या में पर्यटक पधारे हैं। धार्मिक पर्यटन के साथ-साथ हैरिटेज टूरिज्म, वन पर्यटन में पर्याप्त गतिविधियां हैं। इसके साथ-साथ एजुकेशन व हेल्थ टूरिज्म को प्रोत्साहित करने के लिए राशि का प्रावधान किया गया है। प्रदेश में च्छत्रीअन्नज्ज उत्पादन क्षमता देश में सर्वाधिक है। इसे प्रोत्साहन देने के लिए भी व्यवस्था की गई है।

पूर्व रॉ प्रमुख राजिंदर खन्ना को बनाया एडिशनल एनएसए, वी रविचंद्रन को भी मिली अहम जिम्मेदारी

नई दिल्ली। आईपीएस-1990 तमिलनाडु बैच के अधिकारी टीवी रविचंद्रन वर्तमान में विशेष निदेशक (इंटेलिजेंस ब्यूरो) के रूप में कार्यरत हैं। उन्हें उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। टीवी रविचंद्रन के अलावा उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और पूर्व रॉ प्रमुख राजिंदर खन्ना को अतिरिक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। अजीत डोभाल वर्तमान में 2014 से भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं और मोदी सरकार में सबसे भरोसेमंद अधिकारियों में से एक हैं। लगभग एक महीने पहले, डोभाल ने सुझाव दिया था कि देश के विभिन्न केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में रक्षा बलों के लिए चल रही योजना की तरह आपस में संयुक्तता और अंतर-संचालनीयता होनी चाहिए। लगभग दस लाख की ताकत वाले केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में एनडीआरएफ और एनएसजी के अलावा बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ और एसएसबी शामिल हैं और उन्हें भीतरी इलाकों और सीमाओं पर विभिन्न आंतरिक सुरक्षा कर्तव्यों को पूरा करने के लिए तैनात किया गया है।

नए कानूनों के कार्यान्वयन के बाद दंड की जगह न्याय होगा-शाह

नई दिल्ली (एजेंसी)। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देशभर में नए आपराधिक कानून लागू होने के बीच कहा कि अब तीन नए कानूनों के कार्यान्वयन के बाद दंड की जगह न्याय होगा और त्वरित सुनवाई होगी। केंद्रीय मंत्री शाह ने नए आपराधिक कानूनों के संबंध में कहा कि आजादी के 77 साल बाद आपराधिक न्याय प्रणाली स्वदेशी हो रही है और यह भारतीय लोकाचार के आधार पर चलेगी। भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएनए) 2023 सोमवार से पूरे देश में प्रभावी हो गए। इन तीनों कानून ने ब्रिटिश कालीन कानूनों क्रमशः भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह ली है। केंद्रीय मंत्री शाह ने कहा, तीनों आपराधिक न्याय कानूनों के कार्यान्वयन से सबसे आधुनिक आपराधिक न्याय प्रणाली की स्थापना होगी। उन्होंने कहा कि इन कानूनों के लागू होने से दंड की जगह न्याय मिलेगा और देरी की जगह त्वरित न्याय



होगा। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश कालीन पुरानी व्यवस्था में केवल पुलिस के अधिकार सुरक्षित थे, लेकिन अब पीड़ितों और शिकायतकर्ताओं के अधिकार सुरक्षित होने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन तीनों आपराधिक न्याय कानूनों पर चार वर्ष से अधिक समय तक विचार-विमर्श हुआ है। उन्होंने उम्मीद जाहिर कि नए आपराधिक न्याय कानूनों के तहत दोष सिद्ध दर 90 प्रतिशत तक होगी और अपराधों में कमी आएगी।

शाह ने देश के सभी दलों से राजनीतिक से ऊपर उठकर आपराधिक न्याय कानूनों का समर्थन करने की अपील की और कहा कि यदि विपक्ष के किसी भी नेता को नए आपराधिक कानूनों को लेकर कोई चिंता है, तब वह उनसे मिलने के लिए तैयार हैं। उन्होंने बताया कि नई आपराधिक न्याय प्रणाली के बारे में 22.5 लाख से अधिक पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षित करने के लिए 12,000 से अधिक 'मास्टर' प्रशिक्षक तैनात किए गए और नए कानून के तहत पहला केस ग्वालियर में रविवार रात 12 बजकर 10 मिनट पर बाइक चोरी का दर्ज किया गया।

संसद के रिकार्ड से हटाए गए राहुल के भाषण के हिंसक हिंदू वाले अंश

नई दिल्ली। लोकसभा में नेता विपक्ष के रूप में राहुल गांधी के सदन में पहले भाषण के कुछ अंशों को स्पीकर ओम बिरला ने रिकार्ड से हटा दिया है। स्पीकर ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, भाजपा और आरएसएस के हिन्दुत्व को हिंसक. राहुल गांधी बताने संबंधी संबोधन के हिस्से को सदन संचालन के नियम 380 का हवाला देते हुए रिकार्ड से हटाया है। राहुल गांधी ने अपने संबोधन के हिस्से को रिकार्ड से हटाए जाने का कड़ा विरोध करते हुए स्पीकर को पत्र लिखकर साफ कहा है कि उनके भाषण के जिन अंशों को निकाला गया है वह इस नियम के दायरे में नहीं आते क्योंकि इसमें किसी तरह के असंसदीय शब्दों का उपयोग नहीं किया गया है। नेता विपक्ष ने उनकी सुविचारित टिप्पणियों के 'चुनिंदा' हिस्सों को रिकार्ड से हटाने को संसदीय लोकतंत्र के सिद्धांतों के खिलाफ बताते हुए इसे फिर से रिकार्ड में शामिल किए जाने की मांग की है। राहुल ने कहा कि मोदी की दुनिया से चाहे इसे रिकार्ड से हटा दिया जाए, लेकिन सच वही है जो मैंने कहा। आइएनडीआइए के भी कई नेताओं ने राहुल के भाषण के अंशों को सदन के रिकार्ड से हटाए जाने की आलोचना की है।



संपादकीय

नये भारत में बदलाव के कानून, न्याय की ओर

भारतीय न्याय प्रणाली की कमियां को दूर करते हुए उसे अधिक चुस्त, त्वरित एवं सहज सुलभ बनाना नये भारत की अपेक्षा है। मतलब यह सुनिश्चित करने से है कि सभी नागरिकों के लिये न्याय सहज सुलभ महसूस हो, कानूनी प्रावधान न्यायसंगत एवं अपराध-नियंत्रण का माध्यम हो, वह आसानी से मिले, जटिल प्रक्रियाओं से मुक्त होकर सस्ता हो। निश्चित रूप से किसी भी कानून का मकसद नागरिकों के जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति व अधिकारों की रक्षा करना ही होता है। जिससे किसी सभ्य समाज में न्याय की अवधारणा पुष्ट हो सके। 1 जुलाई, 2024 से भारत आपराधिक न्याय के एक नए युग की शुरुआत होने जा रही है। न्याय का एक नया सूरज उदित हो रहा है, जब पूरे देश में लागू हुई भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता तथा भारतीय साक्ष्य संहिता को लेकर उम्मीद करनी चाहिए कि यह बदलाव न्याय की कसौटी पर खरा उतरेंगे। इस दृष्टि से यह कानून से जुड़ी अकल्पित उपलब्धियों से भरा-पूरा अवसर भारत न्याय प्रक्रिया को एक नई शक्ति, नई ताजगी और नया परिवेश देने वाला साबित होगा। उल्लेखनीय है कि कानूनी

बदलाव से जुड़े ये तीनों विधेयक बीते साल संसद में पारित किये गए थे। अंग्रेजों के बनाये कानून क्या स्वतंत्र भारत में साढ़े सात दशक बाद भी लागू रहने चाहिए, यह लम्बे समय से विमर्श का विषय बना रहा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं उनकी सरकार द्वारा न्यायिक व्यवस्था को प्रभावी, आधुनिक, तकनीकी बनाने के लिये, अप्रासंगिक हो चुके कानूनों को बदलने एवं आधुनिक अपेक्षाओं के नये कानून बनाने का साहसिक एवं प्रासंगिक कदम उठाते हुए नए कानून लाने एवं उन्हें लागू करने का बड़ा कदम उठाया है, जो सुखद एवं स्वागतयोग्य है। विपक्षी दलों ने सांस्कृतिक, धार्मिक व भौगोलिक विविधता वाले देश के लिये बनाये गये कानूनों को भले ही व्यापक सार्वजनिक विमर्श के बाद ही लागू किया जाने की अपेक्षा व्यक्त की हो, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि जहां ब्रिटिश काल में बने कानूनों का मकसद दंड देना था, वहीं नये कानूनों का मकसद नागरिकों को न्याय देना है। मौजूदा चुनौतियों व जरूरतों के हिसाब से कानूनों को बनाया गया है। इन कानूनों को बनाने का मूल उद्देश्य अपराधमुक्त समाज की संरचना करना है। इसीलिये अपराधियों को कड़े दण्ड देने का प्रावधान किया गया है। उल्लेखनीय है कि भारतीय न्याय संहिता में विवाह का प्रलोभन देकर छल के मामले में दस साल की सजा, किसी भी आधार पर माँब लिचिंग के मामले में आजीवन कारावास की सजा, लूटपाट व गिरोहबंदी के मामले में तीन

साल की सजा का प्रावधान है। आतंकवाद पर नियंत्रण के लिये भी कानून है। किसी अपराध के मामले में तीन दिन में प्राथमिकी दर्ज की जाएगी तथा सुनवाई के बाद 45 दिन में फैसला देने की समय सीमा निर्धारित की गई है। वहीं प्राथमिकी अपराध व अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम के जरिये दर्ज की जाएगी। व्यवस्था की गई है कि लोग थाने जाए बिना भी ऑनलाइन प्राथमिकी दर्ज कर सकें। यह कहने में कोई हर्ज नहीं है कि इन कानूनों के माध्यम से देश में पुलिस सुधार को भी बल मिलेगा। पुलिस कानून-कायदे के तहत काम करने को विवश या बाध्य होगी। अंततः अब पुलिस को अनुशासित बनाने के साथ-साथ कारगर बनाने की ओर देश ने अपने कदम बढ़ा दिए हैं।

पुलिस प्रशासन की सफलता इसी में है कि तमाम लोगों को यह महसूस हो कि कानून न्यायपूर्ण ढंग से लागू किया जा रहा है। एक पहलू यह भी है कि पुलिस प्रशासन को कुशल और सक्षम बनाने के लिए संसाधनों की कमी आड़े नहीं आए। जिस स्तर की सेवा की उम्मीद लोग पुलिस से कर रहे हैं, उसके लिए सरकारों को पुलिस पर व्यय बढ़ाना होगा। सक्षम और सहयोगी पुलिस हमारे तेज विकास में कारगर होगी। पुलिस को प्रशिक्षित एवं सक्षम बनाने के तंत्र भी नये तरीके से विकसित करने होंगे। एक तरह से इन कानूनी प्रावधानों को सहज एवं सरल बनाने के प्रयास किये गये हैं।

हाथरस हादसे में मौतों की जवाबदेही तय हो

ललित गर्ग

उत्तर प्रदेश के हाथरस में मंगलवार को एक सत्संग के समापन के बाद मची भगदड़ में एक सौ इक्कीस लोगों के मरने एवं सैकड़ों लोगों के घायल होने की हृदयविदारक, दुःखद एवं दर्दनाक घटना ने पूरे देश को विचलित किया है। ऐसी घटनाएं न केवल प्रशासन की लापरवाही एवं गैर जिम्मेदारी को उजागर कर रही है बल्कि धर्म के नाम पर पनप रहे आडम्बर, अंधविश्वास एवं पाखण्ड को भी उजागर कर रही है। ऐसी त्रासदियां एवं दिल को दहलाने देने वाली घटनाओं से जुड़े पाखण्ड बाबाओं की कारगुजारियों से हिन्दू धर्म भी बदनाम हो रहा है, जबकि सैकड़ों लोगों की जान लेने वाले बाबा को हिन्दू धर्म से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। यह हादसा अनेक सवाल को खड़ा करता है, बड़ा सवाल है कि ऐसे बड़े आयोजन में सुरक्षा उपायों की अनदेखी क्यों होती है? सवाल उठता है कि इतना बड़ा आयोजन बिना पुख्ता इंतजाम के किसकी अनुमति से किया जा रहा था? क्या सुरक्षा मानकों का पालन किया गया? क्या इतने बड़े आयोजन की सुरक्षा का जिम्मा पुलिस-प्रशासन का नहीं होता? क्या आयोजन-स्थल पर निकास द्वार, पानी, हवा, वैकल्पित चिकित्सा एवं चिकित्सक, गर्मी से बचने के पुख्ता इंतजाम जरूरी नहीं थे? जवाबदेही तय हो भगदड़ में गयी जानों की। जाहिर है मौतों के बढ़ते आंकड़ों के साथ ही घटना पर लीपापोती की कोशिश भी जमकर होगी, राजनीतिक दल एक-दूसरे को जिम्मेदार ठहराते हुए जमकर राजनीति भी करेंगे। यह तय है कि ऐसे बाबाओं की दुकान बिना राजनेताओं के वरदहस्त के चलनी संभव नहीं है।

हाथरस के सिकंदराराऊ के निकट फुलरई के एक खेत में कथित हरि बाबा के एक दिवसीय सत्संग के दौरान यह हादसा हुआ। इस बाबा से जुड़ी बातें विसंगतियों से भरी हैं। सफेद कोट-पेंट, टाई पहनने वाला यह बाबा कोई पंडित नहीं है न साधु संत है, यह जूता पहनकर प्रवचन देता था। इस बाबा को कितने वेद पुराण का ज्ञान है? यह किस परंपरा से है? इसके गुरु कौन हैं? ऐसे अनेक प्रश्न हैं जो बाबा को शक एवं संदेह के घेरे में लेते हैं। इन्हें हिन्दू बाबा कैसे कहा जा सकता है? हिन्दू धर्म में ऐसा कहा होता है? यह बाबा पहले पुलिस सेवा में थे और जिनका मैनपुरी में भव्य एवं महलनुमा आश्रम है। घटना के बाद बाबा फरार



है। पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। भारत में भोली-भाली जनता को ठगने एवं गुमराह करने वाले ऐसे पाखण्ड बाबाओं की बाढ़ आई हुई है। इस तरह की घटनाएं केवल जनहानि का कारण ही नहीं बनतीं, बल्कि देश एवं धर्म की बदनामी भी करती हैं। इन घटनाओं पर पीड़ितों के प्रति संवेदना व्यक्त करने के बजाए राजनीति करना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और निंदनीय भी।

हाथरस की घटना कितनी अधिक गंभीर एवं चिन्ताजनक है, इसका अनुमान इससे लगाया जा सकता है कि प्रधानमंत्री ने लोकसभा में अपने संबोधन के बीच इस हादसे की जानकारी दी एवं शोक-संवेदना व्यक्त की। दुनिया भर में इस घटना को लेकर दुःख जताया जा रहा है। यह तय है कि हाथरस में इतनी अधिक संख्या में लोगों के मारे जाने पर शोक संवेदनाओं का तांता लगेगा, लेकिन क्या ऐसे हादसों को नियंत्रित करने वाले ऐसे कोई उपाय भी सुनिश्चित कर सकेंगे, जिससे भविष्य में देश को शर्मिंदा करने वाली ऐसी घटना न हो सके? प्रश्न यह भी है कि आखिर धार्मिक आयोजनों में धर्म-कर्म का उपदेश देने वाले लोगों को संयम और अनुशासन की सीख क्यों नहीं दे पाते? कब तक ऐसे आयोजन धन कमाने के माध्यम बनते रहेंगे, जब जब धर्म का ऐसे पाखण्ड एवं पाखण्डियों से गठबंधन हुआ है, तब तक धर्म अपने विशुद्ध स्थान से खिसका है। यह प्रश्न इसलिए, क्योंकि कई बार ऐसे आयोजनों में भगदड़ का कारण लोगों का असंयमित व्यवहार भी बनता है। ऐसा लगता है कि अपने देश में धार्मिक-सामाजिक आयोजनों में कोई इसकी परवाह नहीं करता कि यदि भारी भीड़ के चलते अव्यवस्था फैल

गई तो उसे कैसे संभाला जाएगा? क्या इसलिए कि प्रायः मारे जाने वाले लोग निर्धन एवं गरीब वर्ग के होते हैं?

एक डरावनी एवं संवेदनहीन हकीकत है कि हम ऐसे धर्म एवं धार्मिकता से जुड़े पिछले हादसों से कोई सबक नहीं सीखते। हाल के दिनों में भीड़भाड़ वाले धार्मिक आयोजनों में भगदड़ में लोगों के मरने के मामले लगातार बढ़े हैं। सवाल उठना स्वाभाविक है कि भीड़ के बीच होने वाले हादसों को कैसे रोका जाए। दो साल पहले माता वैष्णो देवी परिसर में भगदड़ में बारह श्रद्धालुओं की मौत हुई थी। अप्रैल 23 में बनारस की भगदड़ में 24 लोग मरे थे। खाटू श्याम में भी भीड़ में दब कर 4 लोगों की मौत हुई। इंदौर में पिछले साल रामनवमी के दिन बावड़ी की छत गिरने से पैंतीस लोग मर गये थे। इसी तरह 2016 में केरल के कोल्लम के एक मंदिर में आग लगने से 108 लोगों की मौत हुई और दौ से अधिक घायल हुए थे। पंजाब के अमृतसर में दशहरे के मौके पर रावण दहन देख रहे साठ लोगों के ट्रेन से कुचलकर मरने की घटना को नहीं भूले हैं। देश में भीड़ की भगदड़ से होने वाले 70 फीसदी हादसे धार्मिक आयोजनों के दौरान ही होते हैं। हाल में दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल से जुड़ा हादसा मुसलमानों के पवित्र स्थल मक्का में हुआ, जहां हज यात्रियों पर गर्मी का सितम इस कदर कहर बना कि 900 से ज्यादा मौतें हुईं, जिनमें 90 भारतीय ने भी जाने गंवाईं।

विडम्बना है कि इन बड़े-बड़े हादसों से न तो जनता कुछ सीख लेती और न ही प्रशासन। यह हैरानी की बात है कि किसी ने यह देखने-समझने की कोई कोशिश नहीं की कि भारी भीड़ को

संभालने की पर्याप्त व्यवस्था है या नहीं? यह मानने के अच्छे-भले कारण हैं कि इस आयोजन की अनुमति देने वाले अधिकारियों ने भी कागजी खानापूती करके कर्तव्य की इतिश्री कर ली। यदि ऐसा नहीं होता तो किसी ने इस पर अवश्य ध्यान दिया होता कि आयोजन स्थल के पास का गड्ढा लोगों की जान जोखिम में डाल सकता है। जैसे-जैसे जीवन में धर्म का पाखण्ड फैलता जा रहा है, सुरक्षा उतनी ही कम हो रही है, जैसे-जैसे प्रशासनिक सर्तकता की बात सुनाई देती है, वैसे-वैसे प्रशासनिक कोताही के सबूत सामने आते हैं, ऐसे आयोजनों में मरने वालों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन हर बड़ी दुर्घटना कुछ शोर-शराबे के बाद एक और नई दुर्घटना की बाट जोहने लगती है। सरकार और सरकारी विभाग जितनी तत्परता मुआवजा देने में और जांच समिति बनाने में दिखाते हैं, अगर सुरक्षा प्रबंधों में इतनी तत्परता दिखाएं तो ऐसे जघन्य हादसों की संख्या घट सकती है।

बहरहाल आने वाले दिनों में जांच के बाद किसी के सिर पर लापरवाही का ठीकरा फोड़ा जाएगा। मगर इन मौतों का कसूरवार कौन है? जिन लोगों ने अपनों को खोया है, उनकी कमी कैसे पूरी होगी? कहा जा रहा है कि यह एक निजी कार्यक्रम था, कानून व्यवस्था के लिये प्रशासन की ड्यूटी लगाई गई थी, लेकिन आयोजन स्थल पर भीतरी व्यवस्था आयोजकों के द्वारा की जानी थी। अब बड़े अधिकारियों का घटना स्थल पर जाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं। उनके तीन मंत्री पहले से वहां पहुंचे हुए हैं। इस एवं इससे जुड़ी कार्रवाइयों से संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता कि उत्तर प्रदेश सरकार ने घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं और दोषी लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है, क्योंकि आमतौर पर यही देखने में आता है कि इस तरह के मामलों में कार्रवाई के नाम पर कुछ अधिक नहीं होता। इसी कारण रह-रहकर ऐसी घटनाएं होती रहती हैं और उनमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु अपनी जान गंवाते हैं। इसके बावजूद कोई सबक सीखने को तैयार नहीं दिखता है। धार्मिक आयोजनों में अव्यवस्था और अनदेखी के चलते लोगों की जान जाने के सिलसिले पर इसलिए विराम नहीं लग पा रहा है, क्योंकि दोषी लोगों के खिलाफ कभी ऐसी कार्रवाई नहीं की जाती, जो नजीर बन सके।

नए कानून एवं प्रावधानों से निश्चित समय पर सुलभ रूप से मिलेगा न्याय : मंत्री कैलाश विजयवर्गीय

इंदौर। प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि आज से लागू किये गये भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक संहिता एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम से अब हर किसी को समय पर सुलभ रूप से न्याय मिलेगा। न्याय में देरी नहीं होगी। दर्ज प्रकरणों में समय पर अनुसंधान होगा। समय पर प्रकरणों का निराकरण किया जायेगा। अनुसंधान, विवेचना, निर्णय, आदेश और अपील के लिये समय-सीमा का निर्धारण किया गया है। इसके लिये हर स्तर पर जवाबदेही भी तय की गई है। उक्त व्यवस्था महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी बड़ा कदम है। महिला एवं बच्चों को नए कानून में विशेष संरक्षण मिला है।

श्री विजयवर्गीय यहां पुलिस कमिश्नरेट इंदौर द्वारा नए कानून-नए प्रावधान, दण्ड से शीघ्र न्याय की ओर विषय पर आयोजित एक संवाद कार्यक्रम को सम्बोधित कर रहे थे। इस अवसर पर महापौर श्री पुष्पमित्र भार्गव, सभागायुक्त श्री दीपक सिंह, पुलिस कमिश्नर श्री राकेश गुप्ता, आईजी बीएसएफ श्री बी.एस. रावत, कलेक्टर श्री



आशीष सिंह, रिटायर्ड डी.जे. श्री विष्णु कुमार सोनी, शहर काजी डॉ. इशरत अली, वरिष्ठ समाजसेवी श्रीमती जनक पलटा सहित समाज के विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधि मौजूद थे। संवाद कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए श्री विजयवर्गीय ने कहा कि नए कानून एवं प्रावधानों से नजरिये में परिवर्तन आयेगा। व्यवस्था के प्रति और

अधिक विश्वास बढ़ेगा। न्याय में देरी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि नए कानून एवं प्रावधानों को प्रभावी रूप से लागू करना चाहिए। इसके लिये सभी स्तर पर सभी संबंधितों को विस्तृत प्रशिक्षण दिया जाये। साधन एवं सुविधाएं मुहैया कराई जाये। कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए महापौर श्री पुष्पमित्र भार्गव ने कहा कि नए

कानून एवं प्रावधानों से अब हम अग्रेजी मानसिकता से बाहर आये हैं। अब हमारा कानून होगा। हमारे प्रावधान होंगे। पहले अग्रेजों के शासन काल में बनाया गया कानून एवं प्रावधान चल रहे थे। अब स्वतंत्र भारत बनाया गया हमारे शासन का कानून एवं प्रावधान है। उन्होंने कहा कि अनुसंधान एवं कानूनी प्रक्रिया सरल हुई है। समाज को लाभ जरूर मिलेगा। कानून का दुरुपयोग भी रुकेगा। कार्यक्रम में पुलिस कमिश्नर श्री राकेश गुप्ता ने नए कानून एवं प्रावधानों की अवधारणा तथा इसके विभिन्न बिंदुओं की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार होगा। संगठित अपराध, आतंकवादी कृत्य, देशद्रोह, मॉबलिचिंग इत्यादि पर प्रभावी नियंत्रण किया जा सकेगा। कार्यक्रम में श्री विष्णु कुमार सोनी, श्री एस.एन. सोनी, श्री नरोत्तम कौरव आदि ने भी नए कानून एवं प्रावधानों के बारे में जानकारी दी। विधि क्षेत्र के विद्यार्थियों ने भी अपने विचार व्यक्त किये। सभी ने इस नए कानून एवं प्रावधानों की सराहना की। कार्यक्रम का संचालन पुलिस अधीक्षक रेल श्रीमती मनीषा सोनी पाठक ने किया।

कलेक्टर सहित अन्य अधिकारियों ने पौधारोपण को लेकर रखी बात

51 लाख पौधे लगाने की तैयारी, सभागायुक्त बोले- व्यापक जनभागीदारी सुनिश्चित करें

इंदौर। जिले में 51 लाख पौधे रोपने की तैयारी जारी है। मंगलवार को कमिश्नर कार्यालय में सभागायुक्त दीपक सिंह की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। सभागायुक्त ने बैठक में शामिल नगर निगम, जिला पंचायत, आईडीए एवं वन विभाग के अधिकारियों से अभियान में व्यापक जन सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए कहा। भोपाल से आए अपर मुख्य प्रधान वन संरक्षक पुरुषोत्तम धीमान ने कहा पौधों की आपूर्ति की व्यापक व्यवस्था वन विभाग की ओर से की जा रही। कलेक्टर आशीष सिंह ने कहा निगम द्वारा अभियान में सामाजिक संगठनों, शैक्षणिक संस्थाओं, व्यापारिक/ वाणिज्यिक संस्थानों को भी जोड़ा गया। जिला पंचायत सीईओ सिद्धार्थ जैन ने कहा जिला पंचायत की ओर डूडू4 से 3 लाख पौधे लगाए जाएंगे। जिले की पांच-छह पहाड़ियां पौधारोपण के लिए चिह्नित की गईं। आईडीए के मुख्य कार्यपालन अधिकारी आरपी अहिरवार ने बताया प्राधिकरण द्वारा 2.10 लाख पौधे लगाए जाएंगे। इसके लिए 21 साइट चिह्नित की गईं।

मध्यमवर्गीय परिवारों को सस्ते फ्लैट बचेगा आईडीए

खजाना भरने को लेकर आईडीए अधिकारियों ने की तैयारी

इंदौर। नगर निगम के बाद अब आईडीए अर्थात इंदौर विकास प्राधिकरण का खजाना भी खाली हो चुका है। आईडीए अधिकारी इसे लेकर काफी चिंतित हैं और खजाना भरने के लिए हर तरह के कार्यों पर विचार किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि आईडीए जल्द ही मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए बनाए गए सस्ते प्लानों की बिक्री कर सकता है। इसके लिए लॉटरी खुलवाए जाने की भी तैयारी की जा रही है। जल्द ही इसके लिए लाटरी सिस्टम से नीलामी की योजना भी बना दी गई है।

आईडीए अधिकारियों के अनुसार ऐसी कुछ योजनाओं के फ्लैटों की बिक्री के लिए लॉटरी निकालने की तैयारी कर रहा है जो सस्ते भी हैं और मध्यमवर्गीय परिवारों की खरीदने की श्रेणी



में भी है इसलिए अब एक बार फिर से आवास उपलब्ध कराने की योजना बनाई गई है। इस मामले को लेकर अधिकारियों का कहना है कि लॉटरी सिस्टम से निकाले जा रहे हैं ताकि छोटे बड़े सभी खाली फ्लैटों के बिकने के बाद विकास प्राधिकरण को बेहतर राशि भी मिल सकती है। इसको लेकर लंबे समय से तैयारी की

जा रही है तो दूसरी ओर यह भी देखा जा रहा है कि कुछ योजना ऐसी भी है। जिसके फ्लैट बार बार बेचने की कोशिश की जाती है परंतु कोई लेने वाला नहीं है। अब लाभ के चलते पहले ही लोगों के पास पैसा नहीं है परंतु फिर भी अपने आवाज की चाह रखने वाले फ्लैट खरीद सकते हैं। इसको लेकर अलग-अलग योजनाओं से खासकर अब फ्लैटों को नीलाम करने की योजना बना दी गई है। अब एक बार फिर से विकास प्राधिकरण अपने काम में लग गया है और जल्द ही कई योजनाओं के टेंडर भी भेजने के लिए निकाले जा रहे हैं। अभी भी कुछ ऐसी योजनाएं भी हैं जिनके फ्लैट से लेकर भूखंड दुकानें आदि भी खाली हैं जिन्हें बेचकर आईडीए अपना खजाना भर सकता है।

टीआई ने समझौते से निपटा दिया था मामला

डीसीपी की फटकार के बाद तीन लोगों पर लूट का केस दर्ज

इंदौर। तिलक नगर थाने की एफआरवी के ड्राइवर और उसके दो साथियों द्वारा दो छात्रों से की गई लूट में डीसीपी अभिनय विश्वकर्मा ने लट का केस दर्ज करवाया है। मामले में एसीपी कुंदन मंडलोई से जांच करवाई तो कई बातें उजागर हुईं जिन्हें टीआई ने दबा दिया था।

एसीपी मंडलोई ने बताया कि 30 जून की दोपहर तिलक नगर थाने की एफआरवी का ड्राइवर दिनेश प्रजापति साथी ड्राइवर सुयश लाड और दोस्त प्रशांत अहिर को गाड़ी में लेकर घूमने निकल गया था। जबकि इस गाड़ी को संबंधित

आरक्षक ने थाने में खड़ी करने के बाद रोजनामचे में गाड़ी जमा कर 'ऑफलाइन' की इंटी दर्ज की थी। जब गाड़ी ऑफलाइन हो जाती है तो उसे फील्ड में नहीं चला सकते। ये बात ड्राइवर दिनेश को पता चली, चाबी उसके पास ही थी, वह थाने में जानकारी दिए बगैर गाड़ी ले गया।

गाड़ी में टक्कर लगने पर छात्रों को धमकाया था-एसीपी ने बताया कि गैरकानूनी ढंग से गाड़ी ले जाने के बाद दिनेश अपने साथियों को घुमाता रहा। इसी दौरान स्कीम-140 में उनकी गाड़ी से छात्र यश लोधी और विनय सिसौदिया की गाड़ी टकरा गई थी। तब दिनेश ने खुद को डीएसपी बताकर दोनों को

धमकाया। उसके साथियों ने भी खुद को पुलिस वाला बताकर उनसे 5,800 रुपए बैंक खाते में ट्रांसफर करवाए, वहीं 2300 रुपए नकद छीन लिए थे। जांच के बाद डीसीपी विश्वकर्मा ने लूट का केस दर्ज करवाया है।

इस तरह सामने आया मामला-महाराष्ट्र से 'जेड-प्लस' सुरक्षा वाले एक नेता आए थे, इसलिए एफआरवी के आरक्षक को होटल एसेशिया में ड्यूटी करने के निर्देश मिले थे, इसलिए उसने गाड़ी ऑफलाइन कर थाने में खड़ी कर दी थी। इधर, अधिकारियों को एफआरवी के मैनेजर ने सूचना दी थी कि थाने की एफआरवी ऑफलाइन होने के बाद भी क्षेत्र में घूम रही है तब यह घटना सामने आई।

भाजयुमो पदाधिकारी शुभम रघुवंशी की हत्या का मामला

भाजपा नेता के हत्यारों की मदद करने के आरोप में प्रहरी गिरफ्तार

माया नामक महिला की तलाश जो बड़े गैंगस्टर के संपर्क में थी

इंदौर। एमजी रोड पुलिस ने भाजयुमो पदाधिकारी शुभम रघुवंशी की हत्या के आरोपितों की मदद करने के आरोप में सेंट्रल जेल के प्रहरी महेंद्रसिंह ठाकुर को गिरफ्तार किया है। आरोपित हत्या में गवाहों को धमकाने के लिए जेल से पत्र लेकर आया था। पुलिस को माया नामक महिला की तलाश है जो बड़े गैंगस्टर के संपर्क में थी। मालवा मिल चौराहा निवासी शुभम रघुवंशी की चार जनवरी को रणजीत हनुमान मंदिर की

प्रभात फेरी में आरोपित यश गोधा, युवराज यादव, कपिल यादव, राहुल चौकसे और कृष्णा प्रजापति ने चाकू मारकर हत्या कर दी थी। युवराज की जमानत हो चुकी है। उसकी दुष्कर्म के आरोप में जेल में बंद आरोपित राकेश चोटी से दोस्ती थी। राकेश ने मंगलवार को जेल प्रहरी महेंद्र को पत्र सौंपा था। पत्र में गवाहों को धमकाने के लिए माया नामक महिला से कहा था कि वह गैंगस्टर युवराज से संपर्क करे। पत्र में युवराज और शुभम के भाई सौरभ के नंबर लिखे थे। जेल प्रहरी ने काल करने में भूल कर दी और सौरभ को ही वाट्सएप पर काल लगा दिए।

नर्सिंग घोटाले पर विधानसभा में हंगामा, मंत्री से इस्तीफा मांगा, सरकार ने दी क्लीनचिट

विधानसभा में पहली बार दिनभर चली ध्यानाकर्षण सूचना पर बहस

भोपाल। नर्सिंग कालेज की मान्यता को लेकर विधानसभा में मंगलवार को सत्तापक्ष और प्रतिपक्ष के बीच दिनभर बहस चली। कांग्रेस के सदस्यों द्वारा प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग से इस्तीफा लेकर सर्वदलीय कमेटी से जांच की मांग पर सत्तापक्ष और प्रतिपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई। सरकार द्वारा मांग नहीं मानने और आसंदी द्वारा कोई निर्देश नहीं देने पर कांग्रेस के सदस्यों ने आसंदी के समक्ष आकर नारेबाजी भी की। मंत्री ज विश्वास सारंग ने भीर साफ कह दिया कि मैं त्यागपत्र कतई नहीं दूंगा।

सदन में नर्सिंग कालेज घोटाले पर चर्चा के दौरान कांग्रेस के सदस्यों ने आरोप लगाया कि नर्सिंग काउंसिल के चुनाव न कराकर मंत्री और अधिकारियों ने मनमर्जी से मान्यता दी। बड़े पैमाने पर अनियमितता हुई। जिन्हें पात्रता नहीं थी, उन्हें पदस्थ किया गया। लाखों विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ। इसमें तत्कालीन चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग की भूमिका रही है, उनका त्यागपत्र लेकर सर्वदलीय कमेटी से जांच कराई जाए। उप मुख्यमंत्री स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा राजेंद्र शुक्ल ने आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए खारिज कर दिया और तत्कालीन चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग को क्लीनचिट देते हुए कहा कि सारंग इस मामले में पूरी तरह से खरे हैं। उन्होंने ईमानदारी के साथ व्यवस्था को सुधारने का काम किया है।

सरकार कार्रवाई करे

सिंधार नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंधार, उप नेता हेमंत कटारे, जयवर्धन सिंह, भंवर सिंह शेखावत समेत प्रतिपक्ष के कई सदस्यों ने आरोप लगाया कि नर्सिंग कालेज को मान्यता देने में सुनियोजित तरीके से



नर्सिंग कालेज घोटाले के विरोध में युवा कांग्रेसियों का सत्याग्रह

भोपाल। प्रदेश में नर्सिंग कालेज घोटाले के विरोध में मंगलवार को युवा कांग्रेस की ओर से बोर्ड ऑफिस चौराहे पर सत्याग्रह आंदोलन की कड़ी में प्रदर्शन किया गया। इसमें शामिल हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि इस घोटाले के कारण प्रदेश के पांच लाख बच्चों का भविष्य चौपट हो गया। इनमें गरीब, आदिवासी, अनुसूचित जाति के बच्चे शामिल थे, जिन्होंने अपना पेट काटकर फीस जमा की थी। उनकी आवाज को कैसे दबा सकते हैं? पटवारी ने मांग की कि मंत्री और उनसे जुड़े लोगों की काल डिटेल निकाली जाए। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में 40 भर्ती परीक्षाओं में घोटाला हुआ है। युवा कांग्रेस के अध्यक्ष मितेंद्र दर्शन ने कहा कि नर्सिंग घोटाले की लड़ाई केवल हमारी और आपकी नहीं है। यह सरकार देश के विद्यार्थियों का भविष्य बेच रही है। प्रदर्शन में पूर्व मंत्री पीसी शर्मा, अरुण श्रीवास्तव, पूर्व विधायक कुणाल चौधरी, सुखेंद्र सिंह, सुनील सर्राफ भी शामिल हुए।

घोटाला किया गया। काउंसिल के चुनाव नहीं कराए गए। आउटसोर्स वाले रखे गए। पेपर लीक मामले में सुनीता शिजू के विरुद्ध ईओडब्ल्यू में प्रकरण है, फिर भी उन्हें रजिस्ट्रार बनाया गया। स्टाफ नर्स को इतनी

बड़ी जिम्मेदारी दी गई। योगेश शर्मा को प्रशासक बनाया, जो नियमानुसार बनाया ही नहीं जा सकता है। तत्कालीन मंत्री विश्वास सारंग ने डीन को पत्र लिखा। जिन कालेजों को अपात्र घोषित किया गया था। उन्हें

मंत्री के निर्देश पर मान्यता दी गई। एक वर्ष में 219 कालेजों को मान्यता दी। हाईकोर्ट के निर्देश पर जांच में धांधली उजागर हो चुकी है। सिंधार के आरोपों पर संसदीय कार्यमंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने प्रश्न उठाए और गलत कहा तो सिंधार ने कहा कि उनके आरोप गलत साबित हुए तो नेता प्रतिपक्ष पद से त्यागपत्र दे दूंगा।

आरोप आधारहीन और तथ्यों से परे-राजेंद्र शुक्ल

प्रतिपक्ष के सदस्यों के आरोपों को उप मुख्यमंत्री स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा राजेंद्र शुक्ल ने खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि 2018 के पहले मान्यता इंडियन नर्सिंग काउंसिल देती थी लेकिन फिर राज्यों की काउंसिल बनी। सीबीआई जांच में जो 66 अनुपयुक्त कालेज पाए गए, उनमें से 39

कांग्रेस सरकार में दी गई थी। आधारहीन और तथ्यों से परे आरोप लगाए गए हैं। दो वर्षों में 480 मान्यता के आवेदन निरस्त किए गए। तीन वर्षों में 502 अस्पतालों का पंजीयन निरस्त किया। मान्यता देने में गड़बड़ी करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। दो रजिस्ट्रार बर्खास्त किए जा चुके हैं तो सातका पदावनत किया है। हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में समिति बनी है। जो भी दोषी होगा कार्रवाई होगी। विद्यार्थियों का राज्य सरकार अहित नहीं होने देगी। दिसंबर 2025 तक एक लाख विद्यार्थियों की परीक्षा कराएंगे। मंत्री विश्वास सारंग को क्लीनचिट देते हुए कहा कि वह इस मामले में पूरी तरह खरे हैं। ईमानदारी के साथ व्यवस्था को सुधारने का काम किया है

रीजनल इन्वेस्टर्स समिट में लघु और सूक्ष्म उद्योगों के विकास पर भी होगी चर्चा: मुख्यमंत्री डॉ. यादव

टीवी चैनल द्वारा किया गया उद्यमियों का सम्मान



भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश के लघु उद्यमियों की सहायता के लिए राज्य शासन तत्पर है। लघु और सूक्ष्म उद्योगों के विकास पर रीजनल इन्वेस्टर्स समिट में चर्चा कर आवश्यक निर्णय लिए जाएंगे। इस माह जबलपुर में हो रही समिट में उद्योग के नवीन क्षेत्रों में निवेश को आमंत्रण दिया जाएगा। खनन आधारित उद्योगों, ग्रामीण कुटीर उद्योगों और रेडीमेंट गारमेंट उद्योग के विकास की काफी संभावनाएं हैं। इन संभावनाओं को साकार करने के लिए क्षेत्र चिन्हित कर लघु उद्योगों की स्थापना की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव एनडी टीवी चैनल की

ओर से स्थानीय होटल मैरियट में एमएसएमई समिट एवं उद्यमियों के सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर चैनल की तरफ से स्थानीय संपादक श्री अनुराग द्वारी ने मुख्यमंत्री डॉ. यादव से विभिन्न विषयों पर चर्चा की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि एक समय उन्होंने उज्जैन में चाय-नाश्ते की होटल का संचालन करते हुए एक व्यवसायी की भूमिका निभाई है।

किसी भी कार्य व्यवसाय को परिश्रम और संयम के साथ साफ-सुथरे ढंग से संचालित कर आत्मनिर्भर होने की भावना किसी भी व्यवसायी या उद्यमी को जीवन में सफलताएं दिलवाती है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में मंत्रीगण द्वारा आयकर की राशि जमा किए जाने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। आज विधानसभा में राज्य सरकार के इस निर्णय का सदस्यों द्वारा मेजें थपथपाकर स्वागत किया गया। स्पीकर श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने विशेष उल्लेख कर इस निर्णय की जानकारी दी। उन्होंने स्वयं भी इनकम टैक्स खुद जमा करने के संकल्प से अवगत करवाया।

सारंग खुद चला रहे थे नर्सिंग काउंसिल, जांच होने तक दें इस्तीफा

भोपाल। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंधार ने कहा नर्सिंग काउंसिल को खुद मंत्री विश्वास सारंग चलाते थे, स्कूलों को कॉलेज बनवा दिया। क्षेत्रफल के मापदंड घटा दिए। आउट सोर्सिंग के कर्मचारियों से काम कराया, जो उनके बंगले और दफ्तर में पदस्थ थे। कोषाध्यक्ष नियुक्त नहीं किया क्योंकि सारे फैसले खुद मंत्री ले रहे थे। अफसरों पर दबाव बनाकर मान्यताएं दिलवाईं। इससे पहले उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे, जयवर्धन सिंह और लखन घनघोरिया ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पेश किया।

मंत्री के पत्र के बाद मान्यता-जयवर्धन सिंह ने दिसंबर 2022 के पत्र का हवाला देते हुए कहा के तत्कालीन मंत्री विश्वास सारंग कि भोपाल के मलय कॉलेज ऑफ नर्सिंग को मंत्री के पत्र के चार दिन बाद ही मान्यता मिल जाती है।

कृषि उपज मंडियों की व्यवस्था के प्रति किसानों का विश्वास बरकरार रहे, वरिष्ठ अधिकारी करें निरीक्षण

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में तुअर के उत्पादन को प्रोत्साहित किया जाए। कोदो-कुटकी के रकबे को बढ़ाने से पानी-बिजली का उपयोग संतुलित होगा तथा फसल चक्र में भी सुधार होगा।

अतः किसानों को कोदो-कुटकी की फसल लेने के लिए प्रेरित करने की आवश्यकता है। फसल चक्र पर ग्रीष्मकालीन फसल लेने के नकारात्मक प्रभाव से भी कृषकों को अवगत कराना जरूरी है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव कृषक हितग्राही मूलक योजनाओं सहित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना तथा कृषि विविधीकरण के लिए किया जा रहे प्रयासों पर संबोधित कर रहे थे। बैठक में किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री ऐदल सिंह कंधाना, मुख्य

सचिव श्रीमती वीरा राणा उपस्थित थीं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि कृषि उपज मंडियों की व्यवस्था को चाक-चौबंद रखने के लिए वरिष्ठ अधिकारी मंडियों के तौल-काँटे, वित्तीय लेन-देन तथा अन्य व्यवस्था का आकस्मिक निरीक्षण करें। यह सुनिश्चित किया जाए कि किसानों के हितों से कहीं भी खिलवाड़ ना हो और मंडी व्यवस्था के प्रति किसानों का विश्वास बरकरार रहे। कलेक्टर कृषि उपज मंडी के संचालन पर भी निगरानी रखें। कहीं पर भी कृषि उपज मंडी में गड़बड़ी पाए जाने पर संबंधित सचिव जिम्मेदार होंगे, उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने वेयरहाउस निर्माण व उपयोग के प्रावधानों में किसानों के हितों को सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक संशोधन करने के निर्देश दिए।

राहुल के बयान पर मप्र विस सभा में हंगामा, कांग्रेस ने किया बहिर्गमन

भोपाल। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के हिंदू समाज को हिंसक बताने वाले बयान पर मंगलवार को मध्य प्रदेश विधानसभा में हंगामा हुआ। सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष के सदस्यों ने एक-दूसरे पर आरोप लगाए। हंगामा बढ़ता देख विधानसभा अध्यक्ष नरेन्द्र सिंह तोमर ने सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिए स्थगित कर दी। विरोधस्वरूप कांग्रेस के सदस्यों ने बहिर्गमन किया।



सदन में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की ओर से नए कानूनों की जानकारी देने पर धन्यवाद प्रकट करते हुए भाजपा के सदस्य एवं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष डा. सीतासरन शर्मा ने राहुल गांधी के बयान का विषय उठा दिया। उन्होंने कहा कि लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता ने हिंदू समाज को हिंसक और नफरत वाला बताया है।

यह आपत्तिजनक है। इसे लेकर माफी मांगी जानी चाहिए। इस पर कांग्रेस के सदस्यों ने आपत्ति जताई। कांग्रेस के सदस्य ओमकार सिंह मरकाम ने कहा कि यदि आप इजाजत दें तो वह वीडियो टेप हम यहां पर रखने के लिए तैयार हैं, जिससे साबित हो जाएगा कि राहुल गांधी के बयान को लेकर भाजपा के लोग भ्रामक जानकारी फैला रहे हैं। इस पर पलटवार करते हुए डा. शर्मा ने कहा कि कहां तक हम यह अपमान सहन करेंगे। 99 सीट लाकर हिलने-डुलने वाले आज सारे समाज को गाली दे रहे हैं।

अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर जोर-जोर से अपनी बात रखने लगे। कांग्रेस के सदस्यों ने बहिर्गमन कर विरोध जताया तो विधानसभा अध्यक्ष 15 मिनट के लिए कार्यवाही ने इस पर दोनों पक्ष के सदस्य स्थगित कर दी।

सनातन विरोधी एजेंडे का हिस्सा है बयान

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल ने कांग्रेस सांसद कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी द्वारा दिए गए वक्तव्य की राहुल गांधी द्वारा हिंदुओं को हिंसक बताना कांग्रेस और 'आएनडीआइए' के सनातन विरोधी हिंडन एजेंडे का हिस्सा है। ऐसा करके राहुल गांधी ने एक बार फिर सनातन को अपमानित करने का प्रयास किया है, जिसके विरोध में देश भर में गुस्सा है। राहुल गांधी के इस संदेश के जो संकेत देश में गए हैं, वो बेहद खतरनाक हैं। प्रहलाद पटेल मंगलवार को प्रदेश भाजपा कार्यालय में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। विधायक भगवान दास सबनानी और प्रदेश भाजपा मीडिया विभाग के अध्यक्ष आशीष अग्रवाल भी उपस्थित थे।

एक पेड़ मां के नाम अभियान

भोपाल में 6 जुलाई को लगाए जाएंगे 12 लाख से अधिक पौधे

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक पेड़ मां के नाम अभियान चलाया है। प्रदेश में एक जुलाई से लेकर 15 जुलाई के बीच अलग-अलग जिलों में इस अभियान को चलाया जायेगा।

भोपाल जिले ने 20 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य लिया है। इसी अभियान के अंतर्गत एक दिन में 6 जुलाई को लगभग 12 लाख से अधिक पौधे लगाने का लक्ष्य तय किया है। ऐसे कार्यों से ही पर्यावरण का माहौल बनता है। ऐसे में पौधारोपण कर न केवल हम पर्यावरण को बचाएंगे बल्कि वानिकीकरण में भी अपनी भूमिका निभाएंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव की मंशानुसार एवं पर्यावरण को बचाने एवं इस अभियान में जन-जन की भागीदारी से विशाल लक्ष्य को हासिल किया जाएगा। भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने सोमवार को

अभियान के संबंध में बैठक लेकर सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ दिए गए लक्ष्य के अनुसार तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में वन विभाग द्वारा बताया गया कि आगामी 6 जुलाई को नौ लाख से अधिक वृक्षारोपण किया जाएगा। जिसके वन विभाग विगत तीन माह से तैयारियां कर रहा है।

वन विभाग द्वारा 9 लाख से अधिक गड्डों की खुदाई एवं अन्य तैयारियों के साथ फेंसिंग की जा चुकी है। सभी चिन्हित स्थानों पर पौधों को पहुँचाया जा रहा है। नगर निगम भोपाल द्वारा 300 से अधिक स्थानों पर एक लाख 20 हजार से अधिक पौधारोपण किया जाएगा। जिसके लिए चयनित स्थानों पर पौधों के लिए गड्डों की खुदाई, ट्री गार्ड की व्यवस्था, पौधों के ट्रांसपोर्टिंग की व्यवस्था एवं आगामी 6 जुलाई को अलग-अलग स्थानों पर सांसद, विधायकगण एवं अन्य जनप्रतिनिधियों द्वारा

किए जाने वाले वृक्षारोपण की तैयारियों की बैठक में जानकारी दी गई। बताया गया कि भोपाल ग्रामीण क्षेत्र के फंदा एवं बैरसिया ब्लॉक में 55-55 हजार पौधारोपण जिला पंचायत भोपाल द्वारा किया जाएगा।

इसके साथ ही अन्य विभागों के द्वारा की जाने वाली तैयारियों की समीक्षा की। कलेक्टर ने सभी भोपाल वासियों से इस अभियान से जुड़ने की अपील की। उन्होंने कहा कि आप अपने परिजन को लेकर, माता जी को साथ लेकर सेल्फी लें। अगर माता जी नहीं हैं तो उनके चित्र के साथ एक पौधा लगाकर सेल्फी ले सकते हैं। अभियान के अंतर्गत निर्धारित वेबसाइट पर भी चित्र अपलोड किया जा सकता है। इससे अन्य लोग प्रेरित होंगे। बैठक में जिला पंचायत सीईओ ऋतुराज सिंह, डीएफओ आलोक पाठक, एडीएम हर्षल पंचोली, हिमांशु चन्द्र सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।



सम्मान : डीजीपी सुधीर सक्सेना ने चाय पिलाने वाले को परोसा खाना

भोपाल। 39 सालों से जो परोस रहे थे चाय, आज उन्हें डीजीपी ने अपने हाथ से खाना परोसा। पुलिस महानिदेशक कार्यालय में सेवाएं प्रदान कर रहे प्रधान आरक्षक (ट्रेड) इंद्र बहादुर, 39 वर्षों की सेवा उपरांत हुए सेवानिवृत्त तो आयोजित कार्यक्रम में डीजीपी सुधीर सक्सेना ने उन्हें सम्मानित किया और अपने हाथों से भोजन की थाली परोसी।

मुख्यमंत्री ने नई न्याय व्यवस्था के क्रियान्वयन के लिए प्रधानमंत्री का माना आभार

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि आज एक जुलाई का दिन महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक है। अंग्रेजों के समय से चले आ रहे तीन कानूनों को बदलकर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में नई व्यवस्था का क्रियान्वयन आरंभ हो रहा है।

इस व्यवस्था के लिए मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मंत्रिपरिषद की ओर से प्रधानमंत्री श्री मोदी को धन्यवाद दिया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि आज से प्रदेश में



परिवहन के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। प्रदेश के नाकों में गुजरात पैटर्न पर चैक-पोस्ट संबंधी नई व्यवस्था लागू की जा रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने विधानसभा के समिति कक्ष में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक से पहले अपने संबोधन में यह बात कही। बैठक वंदे मातरम के गान के साथ आरंभ हुई। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि देश में भारतीय न्याय पद्धति और अवधारणा तथा पंच परमेश्वर की परम्परा के आधार पर

न्याय व्यवस्था स्थापित करने के लिए प्रधानमंत्री श्री मोदी बधाई के पात्र हैं। केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने लगभग चार सौ घंटे के परिश्रम व विभिन्न बैठकों तथा व्यापक विचार-विमर्श के बाद नए कानूनों के प्रारूपों को अंतिम रूप प्रदान किया है। अब भारतीय दंड संहिता को हमारी न्याय परम्परा से जोड़ते हुए न्याय संहिता कहा जाएगा। अंग्रेज तो दंड देने के अधिकारी थे, लेकिन अब हमारी व्यवस्था न्याय की परम्परा को स्थापित करेगी।



जान्हवी
कपूर

Bollywood Update



शहनाज गिल कर रही हैं चोरी छिपे इस स्टार को डेट

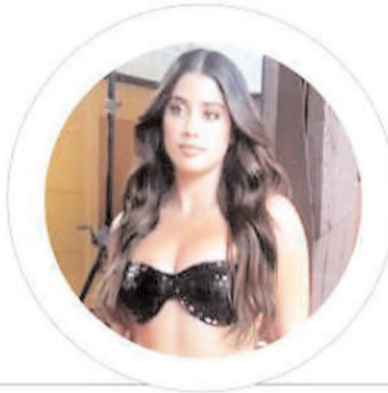
शहनाज गिल अपने ब्यूट अंदाज और अपने बन लाइनस के लिए काफी मशहूर हैं। पंजाब की कैटरिना को नाम से फेमस शहनाज गिल टीवी शो के अलावा बॉलीवुड में भी अपना अच्छा नाम बना चुकी हैं। बात दें कि शहनाज गिल अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ ही अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी सुर्खियों में रही हैं। पिछले दिनों खबर आई थी कि शहनाज गिल राघव जुयाल को डेट कर रही हैं, लेकिन इस बात को सिर्फ एक अफवाह कहकर टाल दिया गया था, लेकिन हाल ही में जानीमानी मीडिया की शेयर की गई रिपोर्ट में उन्होंने खुलासा किया है कि शहनाज

गिल और राघव रिलेशनशिप में हैं। रिपोर्ट मुताबिक राघव और शहनाज कुछ महीनों पहले ही रिलेशन में आए थे। वह दोनों यह पूरी कोशिश करते थे कि दोनों साथ में स्पॉट न किए जाएं। साथ ही में वह इस बात का भी खयाल रखते थे कि दोनों पैस की नजरों से दूर रहे हैं। दोनों कभी भी साथ में मुंबई के पॉश एरिया वाले जगह पर जाने से बचते आए हैं। हालांकि कुछ समय पहले शहनाज गिल और राघव गुरु रंधावा के रिलेशनशिप की खबरों काफी तेज थीं। फिलहाल तो फैंस को अब शहनाज गिल और राघव के ऑफिशियल स्टेटमेंट का इंतजार है। ●

जान्हवी कपूर को किया लोगों ने जमकर ट्रोल

अभिनेत्री जान्हवी कपूर एक शानदार अदाकारा होने के साथ साथ बॉल्ड भी हैं। इसकी झलक वो समय समय पर दिखाती रहती हैं। इस वक्त उनकी कुछ तस्वीरों सामने आ रही हैं जिसमें वो काफी बॉल्ड कपड़ों के साथ कहर ढाती हुई दिख रही हैं। उन्होंने मरमेड लुक लिया है और ऊपर

सिर्फ डिजायनर बिकिनी पहनी हुई है। जान्हवी कपूर इस ब्लैक ड्रेस में बेहद सेक्सी लग रही हैं। जैसे ही तस्वीरों सामने आई लोग इंटरनेट पर खुद को कमेंट्स करने से नहीं रोक पाए। हालांकि कुछ लोग इसपर भी उनको काफी बुरी तरह से ट्रोल कर रहे हैं। ●



पापा बनने के सवाल पर विककी ने तोड़ी चुप्पी

विककी कौशल, तूषि डिमरी और पंजाबी सिंगर एमी विर्क की फिल्म ब्रेड न्यूज का काफी समय से फैंस के बीच बज बना हुआ है। एक लंबे वक्त के बाद विककी कौशल का कॉमेडी अंदाज देखने को मिलने वाला है। ऐसे में इवेंट के दौरान पैपराजी ने विककी कौशल से रियल फादर पर सवाल कर डाला, जिसे सुन एक्टर पहले तो शर्मा गए और फिर उन्होंने इसका मजेदार जवाब देते हुए बोले- जब वो आएगी जो सबसे पहले आपको बताऊंगा। आप पहले ब्रेड न्यूज को एन्जॉय करें। जानकारी के लिए बता दें कि बीते दिनों सोशल मीडिया पर विककी और कटरिना कैफ का एक वीडियो वायरल हुआ था,

जिसमें ये कपल लंदन की सड़कों पर एक-दूसरे का हाथ थामे चलता नजर आया था। इस वीडियो को देख सोशल मीडिया पर कटरिना कैफ के प्रेग्नेट होने की अफवाह उड़ने लगी थी। हालांकि, जब वह वापस लौटी तो एयरपोर्ट पर नजर आई, जिसके बाद से उनकी प्रेग्नेसी की अफवाहें खारिज हो गई।
कव रिलीज होगी ब्रेड न्यूज
तूषि डिमरी और विककी कौशल पहली बार के साथ पर्दे पर फिल्म ब्रेड न्यूज में नजर आएंगे। यह फिल्म 19 जुलाई को रिलीज होने वाली है। फिल्म के निर्देशक राज मेहता हैं। ये एक कॉमेडी फिल्म है। फिल्म को वास्तविक घटना से प्रेरित बताया जा रहा है। ●

महाराज के साथ इंटीमेट सीन पर किशोरी ने किया रिप्लेट, बोली-मैंने कुछ गलत नहीं किया

आमिर खान के बेटे जुनैद खान, शालिनी पांडे, शारवरी और जयदीप अहलावत स्टार फिल्म महाराज नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो चुकी है। फिल्म को लेकर सितारे जमकर तरीफें भी बटोर रहे हैं, लेकिन फिल्म को लेकर जमकर कॉन्ट्रोवर्सी भी देखने को मिल रही है। बता दें कि महाराज को Imdb ने 10 में से 6.3 रेटिंग दी है। महाराज फिल्म की लीड एक्ट्रेस शालिनी पांडे ने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया है जो सोशल



मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस इंटरव्यू में वह चरण सेवा के अपने एक्सपीरियंस को लेकर बात करती हैं। उन्होंने इंटरव्यू में बताया कि इस सीन को शूट करने के बाद उनके मन पर कैसा प्रभाव पड़ा था। महाराज का चलता है राज महाराज फिल्म में जयदीप अहलावत जदुनाथ की भूमिका में हैं। जिनका मानना होता है कि महिलाओं को चरण सेवा की रस्म करनी चाहिए। इस रस्म के तहत उन्हें खुद को महाराज

के लिए समर्पित करना होता है। महाराज ऐसा भ्रम फैलाते हैं कि युवतियों को उनके साथ बंद कमरे में समय बिताना चाहिए। समाज महाराज पर अधिक विश्वास करता है और हर कोई महाराज का कहना मानता है।
वेचैन हो गई थीं शालिनी पांडे
जब तक मैंने इस सीन को नहीं किया था तब तक मुझे नहीं पता था कि यह मेरे मन पर इस तरह से प्रभाव डालेगा। क्योंकि जैसे ही मैंने इस सीन को शूट किया मैं घबरा गई। ●



समर वेकेशन में घर पर ही बच्चों के साथ ऐसे बिताएं क्वालिटी टाइम

मई-जून के महीनों में घूमने की बात ही अलग है क्योंकि भारत के अधिकतर स्कूल इस दौरान बंद होते हैं। समर सीजन को फैमिली ट्रिप के लिए बेस्ट माना जाता है। फैमिली में अगर बच्चे हैं और उन्हें घुमाने के लिए पेरेंट्स गर्मी की छुट्टियों का इंतजार करते हैं। कई बार ऐसी सिचुएशन भी बन जाती है कि पेरेंट्स या फैमिली गर्मियों में घूमने के लिए बाहर नहीं जा पाते हैं। ऐसे में बच्चे या फैमिली निराश भी हो जाते हैं। क्या आप भी इस बार बाहर या दूसरे शहर में घूमने के लिए नहीं जा पा रहे हैं। चलिए आपको बताते हैं कि कैसे आप घर पर रहकर भी बच्चों के साथ समर वेकेशन को एंजॉय या यादगार बना सकते हैं।

एक्टिविटीज

छोटी-छोटी कई ऐसी फ्लेइंग एक्टिविटी होती हैं जिन्हें बच्चा एंजॉय करता है और इनसे काफी कुछ सीखता भी है। अपने बच्चे के इंटरैस्ट के हिसाब से उसे एक्टिविटी में बिजी करें। अगर उसे पेंटिंग पसंद है तो इससे जुड़ी चीजें लाकर दें। म्यूजिक लवर्स को इसे सीखाने के लिए इंस्ट्रूमेंट लाकर दिया जा सकता है। जिसमें आपके बच्चे का मन लगता है अगर उसे वो चीज दी जाए तो वह पूरे सीजन



बिजी रह सकता है।

गार्डनिंग

अगर आपके घर में गार्डन या पौधे हैं तो आप समर में बच्चे से इनकी देखभाल करवा सकते हैं। बच्चों को पौधों में पानी देना और इनकी देखरेख करना बहुत पसंद है। ये एक तरह की यूनिवर्सल एक्टिविटी है जिसे आपका बच्चा इंटरैस्ट के साथ करेगा और इसमें एंजॉयमेंट भी फील करेगा।

पार्क जाएं

अपने शहर से बाहर नहीं जा पा रहे हैं तो इसमें परेशान न होएं। इसकी जगह आप अपनी फैमिली के साथ पार्क का रूटीन बना सकते हैं। हरे भरे पार्क में ताजी हवा और खुला माहौल मिलता है और इससे दिमाग में पॉजिटिविटी आती है। समर वेकेशन ही नहीं आपको हमेशा पार्क का रूटीन फॉलो करना चाहिए।

पिकनिक है बेस्ट

एक समय था जब फैमिली कम खर्च में एंजॉय करने के लिए अपने घर के आसपास पिकनिक पर जाया करती थी। परिवार के साथ टाइम बिताने का ये तरीका बेस्ट है। ●

गर्मी में परफेक्ट लुक पाने के लिए इन सनग्लासेज को ट्राई करें

स

नग्लासेज फैशन एसेसरीज का एक अहम हिस्सा है, जो न सिर्फ आंखों की तेज धूप, डस्ट और गर्मी से हिफाजत करते हैं बल्कि लुक में भी निखार लाते हैं। गोरे-गोरे मुखड़े पर काला-काला चश्मा ओल्ड फैशन की बात हो गई, क्योंकि अब ट्रेंड बदल चुका है। आजकल रंग-बिरंगे और स्टाइलिश फ्रेम वाले चश्मों में खूब बिक रहे हैं जो देखने में तो अच्छे लगते हैं, लेकिन वो आपकी आंखों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। सनग्लास खरीदते समय कई बातों का ध्यान रखने की जरूरत है। लेंस और फ्रेम का मेल ठीक है या नहीं, साथ ही सनग्लास आपके चेहरे को भी सूट कर रहा है या नहीं। आप भी अगर सनग्लास में परफेक्ट लुक पाना चाहती हैं तो इन्हें खरीदते समय कुछ खास बातों का ध्यान रखें। आइए जानते हैं कि कैसे खरीदें गर्मी में सनग्लास जो आपके चेहरे को सूट करें।



गोल फेस के लिए बेस्ट है ओवरसाइज

जिन लड़कियों का चेहरा गोल होता है उनके लिए राउंड शोप ओवरसाइज सन ग्लासेज बेस्ट होते हैं, इन्हें पहन कर लड़कियों का चेहरा उभरा हुआ दिखता

है। ब्लैक कलर का सनग्लास आपके लिए एक दम परफेक्ट है। इन सनग्लासेज को आप धूप और धूल से बचने के लिए बाइक की सवारी करने में भी पहन सकती हैं। यह सूर्य की हानिकारक यूवी किरणों से भी आपकी आंखों की हिफाजत करता है। अगर आपको ओवरसाइज सनग्लास पसंद हैं

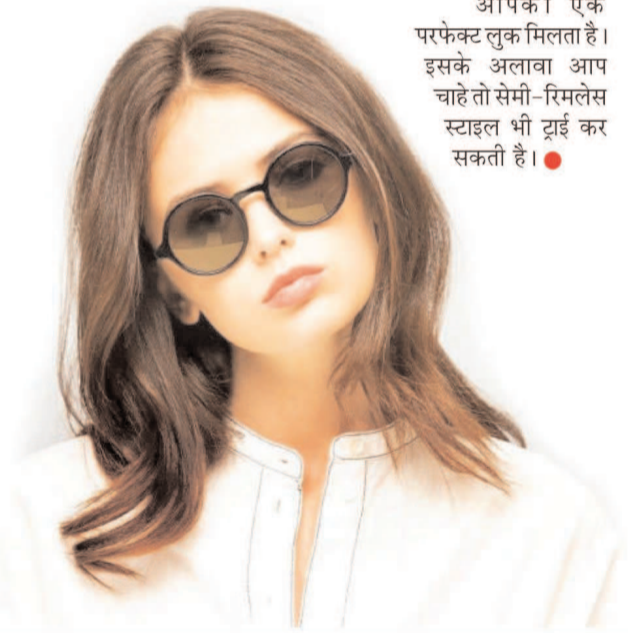
तो इसे आप जरूर ट्राई करें। स्क्रैप शोप के सनग्लासेस चेहरे की लंबाई और चौड़ाई लगभग बराबर हो तो ये स्क्रैप फेस होता है। ऐसे चेहरे पर स्क्रैप शोप के बड़े सनग्लासेस अच्छे लगते हैं। यह ग्लासेस आप कलर फ्रेम वाले ग्लासेस, ओवल, राउंड और टियरड्रॉप शोप में खरीद सकते हैं। अगर आप खुद को एक अलग अंदाज देना चाहती हैं तो इसके लिए स्क्रैप सनग्लासेस का इस्तेमाल भी कर सकती है।

रेक्टंगुलर, ओवल, राउंड-बटरफ्लाइ

ओवल फेस वाले लोगों को बड़े फ्रेम के ग्लासेज से परहेज करना चाहिए, क्योंकि ये आपकी खूबसूरती को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। ऐसे चेहरे वाले लोगों पर रेक्टंगुलर, ओवल, राउंड-बटरफ्लाइ फ्रेम के सनग्लासेज काफी स्टाइलिश दिखते हैं। इस तरह के ग्लासेज को आप अपनी पसंद और स्किन टोन के हिसाब से चुन सकती हैं।

राउंड शोप सनग्लासेज

चौड़े माथे की लड़कियों के लिए राउंड शोप वाले सनग्लासेज अच्छे रहते हैं, इससे आपको एक परफेक्ट लुक मिलता है। इसके अलावा आप चाहे तो सेमी-रिमलेस स्टाइल भी ट्राई कर सकती है। ●



इस तरह घर पर बना सकते हैं जामुन की आइसक्रीम

आ

प सभी ने आइसक्रीम तो कई खाई होगी लेकिन क्या कभी जामुन से बानी आइसक्रीम खाई है? यदि नहीं खाई तो कोई बात नहीं। आज हम आपको बताएंगे कि इसे घर पर कैसे बना सकते हैं।

सामग्री - 4 चम्मच काली जामुन, बीज निकले हुए 2 1/2 लो फेट मिलक 2 चम्मच कार्न फ्लोर 1 चम्मच शुगर फ्री या अन्य कोई शक्कर का विकल्प।

विधि - सबसे पहले कार्न फ्लोर और आधा कप दूध एक कटोरे में मिक्स करें और किनारे रख दें। फिर बाकी का बचा दूध एक नॉनस्टिक पैन में मध्यम आंच पर लगभग 4 मिनट तक गरम कीजिये। इसी दूध में कार्न फ्लोर मिलक वाला मिश्रण चलाते हुए मिलाइये। इसे 4 मिनट तक पकाना है। फिर इसे किनारे रख दीजिये। जब यह दूध ठंडा हो जाए तब इसमें जामुन और शक्कर मिलाइये। इस मिश्रण को एक एल्यूमीनियम कंटेनर में डालें और इसे एल्यूमीनियम फोइल से ढंक कर फ्रिजर में 6 घंटे के लिये रख दें। फिर इस मिश्रण को निकाल कर ब्लेंडर में डाल कर स्मूथ बनाइये और फिर इसे उसी एल्यूमीनियम कंटेनर में वापस भर दीजिये और एल्यूमीनियम फोइल से कवर कर के फ्रिजर में 10 घंटों के लिये जमने के लिये रख दें। 10 घंटे के बाद इसे निकालिये और सर्व कीजिये। ●



युगपुरुष धाम में 5 बच्चों की मौत, 2 की हालत गंभीर, 38 भर्ती

इंदौर। युगपुरुष धाम में कुछ बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। चार दिन में अब तक पांच बच्चों की मौत हो गई। मंगलवार को 38 बच्चों को चाचा नेहरू अस्पताल में भर्ती कराया।

पंचकुड़िया रोड स्थित श्री युगपुरुष धाम आश्रम की प्राचार्य डॉ. अनिता शर्मा ने कहा कि आश्रम में 204 बच्चे हैं। इनमें से पांच की मौत हुई। 29 का इलाज जारी है। जिन पांच बच्चों की मौत हुई, उनमें से 2 को मिर्गी आती थी। अन्य दो की मौत के पीछे ब्लड इन्फेक्शन और फूड पायजनिंग की आशंका जताई है। मृत बच्चों के नाम शुभम उर्फ करण, आकाश, शुभ, दिव्या और छोटा गोविंद हैं। सभी की उम्र 5 से 15 साल के बीच है।

कलेक्टर ने एसडीएम को हटाय़ा- कलेक्टर आशीष सिंह ने विस्तृत जांच के आदेश दिए। वे मंगलवार सुबह भर्ती बच्चों की जानकारी लेने पहुंचे, दोपहर में आश्रम भी गए। इधर, घटनास्थल पर तैनात मल्हारगंज एसडीएम ओमप्रकाश नारायण बड़कुल को शाम को हटा दिया गया। बड़कुल इस संवेदनशील विषय पर ड्यूटी के दौरान ठहाके लगाते दिखे थे, जिनका वीडियो वायरल हुआ था।

डॉ.निधि वर्मा को सौंपा दायित्व- कलेक्टर आशीष सिंह ने एसडीएम ओमप्रकाश नारायण बड़कुल को तत्काल प्रभाव से जिला निर्वाचन कार्यालय में अटैच किया गया है। एसडीएम का हंसी-ठिठोली वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद कार्रवाई की गई। प्रभारी डिप्टी कलेक्टर डॉ. निधि वर्मा को



अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मल्हारगंज का दायित्व सौंपा है।

कांग्रेस ने जांच कमेटी बनाने की मांग की- मामले को लेकर कांग्रेस नेता राकेश सिंह यादव का कहना है कि आश्रम में बच्चों की मौत के पीछे अवैध ड्रग ट्रायल की प्रबल संभावना है। अनाथ आश्रम और ट्रस्ट के हॉस्पिटल के तीन माह के सीसीटीवी फुटेज जब्त किए जाएं। मामले की जांच के लिए सीएम उच्चस्तरीय कमेटी बनाए।

घटना में दोषी पाए जाने पर संबंधित के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाए।

हर बच्चे की जांच आश्रम में- चौथी मौत के बाद प्रशासन ने हर बच्चे का चेकअप कराने का फैसला किया। कलेक्टर के निर्देश टल और चाचा नेहरू अस्पताल के विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम

आश्रम भेजी गई। कलेक्टर खुद भी मौजूद रहे। बता दें कि आश्रम में 204 बच्चे थे, जिनमें 27 से ज्यादा प्रभावित हुए हैं। चूँकि आश्रम के लिए मानसिक दिव्यांग के डॉक्टर हैं लेकिन घटना के बाद उनकी भूमिका संदेहास्पद हो गई है। इस कारण प्रशासन ने अगले 15 से 30 घंटे के लिए प्लान इ बना लिया है। सरकार द्वारा नियुक्त अधिकृत डॉक्टर आश्रम के हर बच्चे को जांचेंगे, परखेंगे। चाहे दिव्यांग बच्चा कुछ जता पाए या नहीं। डॉक्टर को मामूली भी संदेह होता है तो उसकी जिम्मेदारी होगी कि तुरंत ऑब्जर्वेशन में भिजवाए। इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने से कहा ह्यअब तक चार बच्चों की मौत हुई है। करीब 38 भर्ती हैं। हर जान को बचाने के लिए हमने नए प्लान पर काम शुरू कर दिया है। जो बच्चे आश्रम में हैं, उनके खान-पान को

भी मॉनिटरिंग में लिया गया है। उन्होंने माना कि मानसिक दिव्यांग होने से बीमार बच्चों को ट्रेस करने में परेशानी आई थी।

मौत की वजह साफ नहीं- प्रशासनिक सूत्रों ने बताया चारों बच्चों के पोस्ट मार्टम की शार्ट पीएम रिपोर्ट मंगलवार शाम को आ गई है। इसमें साफ नहीं हुआ है कि मौत की वजह क्या है? प्रशासन इसे प्राथमिक तौर पर फूड पॉइजनिंग ही मान रहा है। अब विस्तृत जांच के लिए विस्तरा भेजा गया है। आश्रम के पानी और भोजन पर रोक- चार बच्चों की मौत में फूड पॉइजनिंग की आशंका के बाद अब आश्रम के खाने और पानी की मनाही कर दी गई है। अब शेष करीब 180 बच्चों को पानी और खाने की जांच रिपोर्ट आने तक यहां का खाना नहीं दिया जाएगा। पानी-भोजन की डिलीवरी बाहर से ही कराई जाएगी। 5 से लेकर 18 साल तक के बच्चे बीमार- जो बच्चे बीमार हैं, उनकी उम्र 5 से लेकर 18 साल तक की है। इनमें सबसे ज्यादा 12 से 18 के बीच के हैं। जांच अधिकारी ने बताया कि जिन बच्चों के हाथ-पैर में ठंडक मिली है या फिर बुखार या घबराहट के हल्के लक्षण महसूस हो रहे हैं, हम उन्हें अपने स्तर पर ट्रेक करके अस्पताल भिजवाने के निर्देश हैं।

मानसिक रूप से कमजोर बच्चों का आश्रम है- पंचकुड़िया रोड स्थित श्री युगपुरुष धाम आश्रम में मानसिक दिव्यांग बच्चों को रखा जाता है। यहां अलग-अलग जिलों से बच्चों को चाइल्ड लाइन या अन्य माध्यम से सौंपा जाता है। यहां

फिलहाल 217 मानसिक दिव्यांग बच्चे (101 बच्चे और 116 बच्चियां) हैं। सरकारी रिकॉर्ड में सभी बच्चों के साथ मां का नाम यहां की आचार्य डॉ. अनिता शर्मा लिखा हुआ है। जो बच्चे 10-15 साल पहले आए थे, इन्हीं में से 18 बेटियां एक-एक बच्चे की जिम्मेदारी संभाल रही हैं।

आश्रम संचालिका और एसडीएम लगाते रहे ठहाके- आश्रम की संचालिका डॉ. अनिता शर्मा और एसडीएम ओमनारायण सिंह का वीडियो जो सामने आया है। उसमें दोनों घटना स्थल पर निरीक्षण के दौरान ठहाके लगाते दिखे। वीडियो में 7 सेकेंड पर यह दृश्य साफ नजर आ रहा है। वीडियो सामने आने के बाद कलेक्टर ने एसडीएम को पद से हटाकर अटैच कर दिया है।

आश्रम संचालिका बोली- आश्रम में मौजूद सभी बच्चे स्वस्थ- जिन तीन बच्चों की मौत हुई है उनमें से दो को मिर्गी आती थी। यहां के 204 में से 51 बच्चों को मिर्गी आती है। इनकी उम्र कम ही होती है। कई बार मिर्गी आते समय ही उनकी मौत हो जाती है। पोस्टमार्टम के बाद स्थिति और क्लियर हो जाएगी। यहां के हर बच्चे की प्रॉपर निगरानी करते हैं।

एडीएम बोले- फूड सेफ्टी टीम जांच कर रही, डॉक्टर भी पहुंचे- एडीएम राजेंद्र रघुवंशी ने मीडिया बताया कि आश्रम में 204 बच्चे हैं। इनमें से तीन की मौत हो गई है। 12 बच्चे भर्ती हैं। बाकी बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए डॉक्टरों की टीम पहुंच गई है। वहीं फूड सेफ्टी टीम भी जांच कर रही है।

प्रदेश में अब नया किरायेदारी अधिनियम 2023 लागू होगा

किरायेदारों के विवादित मामले कलेक्टर-एसडीएम सुलझाएंगे

तीन माह में होगा निराकरण, तीन पेशी पर नहीं आये तो एक तरफा फैसला

इंदौर। डिजास्ट अधिनियम 2023 को विधानसभा के अगले सत्र में पारित करवा कर लागू किया जाएगा। इस सत्र में इस अधिनियम को लेकर विधि विभाग द्वारा इसका खाका प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

इसके अंतर्गत अब किरायेदारों के विवादित मामले कोर्ट की बजाए कलेक्टर और एसडीएम स्तर पर सुने जाएंगे। अभी तक किरायेदार और मकानमालिक के विवाद सीधे न्यायालय में जाते थे और इसकी सुनवाई में लंबा समय लगता था। अब सरकार ने जिला प्रशासन के अधीन एक अधिकरण बनाने का निर्णय लिया है जहां किराये पर देने के लिए संपत्ति मालिक इसका रजिस्ट्रेशन करवा सकेगा। रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए एक पोर्टल भी तैयार किया जा रहा है जिसमें लोग अपनी संपत्ति का पंजीयन करवा सकेगा। प्रापटी मकानमालिक और किरायेदार के विवाद अब सीधे न्यायालय में नहीं जाएंगे इसकी सुनवाई के लिए सरकार किराया न्यायालय और किराया अधिकरण बनाने जा रही है पहले कलेक्टर कार्यालय में आवेदन देना होगा, जिससे लोगों को त्वरित न्याय मिल सके। न्यायालय में कलेक्टर और एसडीएम को अधिकृत किया जा रहा है जो सुनवाई करेंगे। इसने प्रत्येक जिला न्यायालय में पदस्थ किसी एक न्यायाधीश को

प्राधिकारी बनाया जाएगा। विवाद की स्थिति में किरायेदार और मकान मालिक इन्हीं न्यायालय में अपील कर सकेंगे। इसमें अगर वादी या प्रतिवादी में से कोई भी पेशी पर तीन बार तक नहीं पहुंचेगा तो इसका एक तरफा फैसला हो जाएगा। आदेश होने के बाद कब्जा दिलाने का काम भी जिला प्रशासन करेगा। इसमें किराये से संपत्ति देने के लिए संपत्ति मालिक अब जिला प्रशासन के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करा सकेगा। पक्षकार को शपथ पत्र से न्यायालय और अधिकरण होगा इसके साथ संपत्ति का एक प्रतिशत स्टाम्प शुल्क जिला प्रशासन में जमा होगा। कब्जा लेने से 24 घंटे पहले किरायेदार को इसकी सूचना मकान मालिक को देना होगी।

एक माह के अंदर किरायेदार अगर कोई संपत्ति को खाली नहीं कर रहा है तो इसकी सूचना किरायेदारी न्यायालय को देना होगी। अभी तक किरायेदार और मकान मालिक के विवाद सीधे न्यायालय में जाते थे जहां मकानमालिक और किरायेदार के पचास और सौ रुपये के स्टाम्प में अनुबंध को न्यायालय स्वीकार नहीं करता था। इस नये अधिनियम में मकान मालिक या दुकान मालिक टूटफूट होने पर उसे दुरुस्त करा सकेगा इसमें किरायेदार उसे रोक नहीं सकता है।

भंवरकुआं में 3 अवैध इमारतें ढहाई, इनमें चल रहे थे होस्टल



इंदौर। शहर में अवैध रूप से किए जा रहे निर्माण पर प्रशासन और नगर निगम की संयुक्त कार्रवाई जारी है। भंवरकुआं क्षेत्र के सर्वानंद नगर में अवैध निर्माण हटाने की कार्रवाई एक पखवाड़े से जारी है। अब तक तीन बिल्डिंग तोड़ चुके प्रशासन ने मंगलवार को निगम और पुलिस टीम के सहयोग से सर्वानंद नगर, हरगोविंद नगर और भूरा नगर में तीन बड़ी बिल्डिंगों पर बुलडोजर चलवाया। ये तीनों भवन करीब 10 हजार वर्गफीट पर अवैध रूप से बनाए गए थे। ये भवन ग्रीन बेल्ट पर बने थे और इनमें होस्टल संचालित किए जा रहे थे। कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया पीपल्यापाला क्षेत्र के सर्वानंद नगर में ग्रीन बेल्ट

की जमीन पर निर्माणाधीन तीन होस्टल जमींदोज किए गए। जून इंदौर एसडीएम घनश्याम धनगर ने बताया इस कार्रवाई में 6 हजार वर्गफीट में बनाए जा रहे एक तीन मंजिला होस्टल भवन से अतिक्रमण ढहाया गया। इसी तरह दो-दो हजार वर्गफीट पर निर्माणाधीन दो और भवनों के अवैध निर्माण भी ध्वस्त किए गए।

इन लोगों ने कर रखे थे अवैध निर्माण- भवन अधिकारी नागेंद्रसिंह भदौरिया ने बताया जोन 13 के वार्ड 74 स्थित ये तीन निर्माण निगम के 100 से ज्यादा कर्मचारियों की मदद से तोड़े गए। हरगोविंद नगर में भवन स्वामी राजेंद्र कौर अरोरा और हरप्रीत कौर अरोरा द्वारा 6 हजार वर्गफीट में जी प्लस 1 पर बिना अनुमति अवैध रूप से निर्मित होस्टल को पोकलेन व जेसीबी से तोड़ा गया। वार्ड 74 में जितेंद्र तलरेजा द्वारा 2500 वर्गफीट पर अवैध रूप से बिना अनुमति निर्माणाधीन अवैध होस्टल तोड़ा गया। इसी तरह भूरा नगर में भवन स्वामी एपी गोस्वामी द्वारा बिना अनुमति 2 हजार वर्गफीट पर जी प्लस-3 भवन का निर्माण किया गया। इसमें 4 जेसीबी, 6 पोकलेन का उपयोग किया गया। कलेक्टर ने बताया यहां कुछ और अवैध निर्माण चिह्नित किए हैं। जल्द ही उन पर भी कार्रवाई होगी।